

जी.एस.टी. 2.0 (रिफॉर्म्स का नया दौर) केवल आशा पर निर्भर नहीं है

वित्त मंत्री आशा कर रही हैं कि इन रिफॉर्म्स के कारण रोज़मर्रा का सामान सस्ता होगा, और डिमाण्ड (मांग) बढ़ेगी

-अंजन राॅय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4 सितम्बरा जीएसटी काउन्सिल द्वारा किए गए सुधार पूरे देश के लिए एक बड़ा बजट जैसा कदम है। यह कदम न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि राज्यों के बजट को भी तय करने वाला अहम कारक बनेगा। माल और सेवा कर यानी जीएसटी ने सभी अप्रत्यक्ष करों (इनडायरेक्ट टैक्सज़) को मिलाकर एक साझा कर ढांचा बनाया था और अब यह केंद्र व राज्यों दोनों की कुल आय का बड़ा हिस्सा है। दरअसल, जीएसटी की दरों में व्यापक बदलाव और कर की श्रेणियों को घटाने की कोशिश के पीछे क्या तर्क है? सबसे पहले, यह कर दरों की श्रेणियों को सरल बनाने और घटाने के वादे को पूरा करता है। यह सुधार, 2017 में जीएसटी लागू करते समय शुरू हुए व्यापक कर सुधारों का ही हिस्सा है। उस समय देश में केंद्र और राज्यों की कई अलग-अलग कर व्यवस्थाएँ थीं जिन्हें मिलाकर एक समान “कर प्रणाली” यानी जी.एस.टी., बनाई गई।

- विदेश में (विशेषकर अमेरिका में) ऊंची टैरिफ के कारण भारतीय सामान के निर्यात को धक्का लगेगा। वित्त मंत्री चाहती हैं कि विदेशों में मांग घटने से व्यापार में आई कमी की भरपाई, देश में स्थानीय खपत बढ़ने से पूरी की जा सकेगी।
- टैक्स घटा कर, “इन्टर्नल डिमाण्ड” बढ़ाने का फार्मूला कई देश पहले ही अजमा चुके हैं। उदाहरण के लिये, अमेरिका में भी राष्ट्रपति रीगन की सरकार ने स्थानीय टैक्स काफी घटाये थे, तथा इससे देश में “इन्टर्नल डिमाण्ड” आंकलन से भी ज्यादा बढ़ी थी, और अमेरिका की इकॉनमी के वारे-न्यारे हो गये थे।
- पर अगर भारतीय उद्योगपतियों ने बढ़ती डिमाण्ड की पूर्ति के लिये, नया इन्वेस्टमेंट करके औद्योगिक क्षमता नहीं बढ़ाई, तो सप्लाई की पूर्ति नहीं कर पायेंगे और मंहगाई बढ़ेगी, और इकॉनमी में उल्टा चक्कर घूमने लगेगा और अगर इकॉनमी इस व्यूहरचना में फंस गई तो उससे उबरना बहुत मुश्किल होगा।

उस समय वादा किया गया था कि केवल दो टैक्स स्लैब होंगे, लेकिन व्यवहारिक कारणों से चार स्लैब लागू किए गए और लक्ष्य रखा गया कि धीरे-

प्रतिशत का “सिन टैक्स” शामिल है। औसतन, जीएसटी केंद्र और राज्यों की कुल आय का लगभग 44 प्रतिशत है, तथा राज्यों की आय में इसका हिस्सा और भी अधिक है। इसलिए दरों में बदलाव से राज्यों की वित्तीय स्थिति केंद्र से ज्यादा प्रभावित हो सकती है। चूंकि जीएसटी की दरें काउन्सिल तय करती है और न तो केंद्र और न ही राज्य इन्हें अकेले बदल सकते हैं, इसलिए ये घोषणाएँ एक ठोस व स्थाई ढांचा देती हैं जिसके भीतर बजट बनाना अनिवार्य होगा। नए जी.एस.टी. सुधारों की घोषणा से बजट बनाने के लिए एक आधार तय हो गया है। जीएसटी 2.0 कहलाने वाले इस स्लैब सुधार की घोषणा पुराने बजट घोषणाओं जैसी लगी, जहाँ कर में बदलाव के असर से रोजमर्रा की चीजों की कीमतें ऊपर-नीचे होती थीं, सिगरेट मंहंगी, बीड़ी सस्ती, एसी मंहंगे, डीजल सस्ता और इसी तरह। सवाल है कि अभी ये बदलाव क्यों? दरअसल, स्लैब घटाने और (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एस. आई. भर्ती : एक और अभ्यार्थी गिरफ्तार

जयपुर, 4 सितम्बरा। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने पुलिस उपनिरीक्षक (एसआई) भर्ती परीक्षा-2021 मामले में कार्रवाई करते हुए, एक और अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित ने परीक्षा से पहले लीक सॉल्वड पेपर पढ़ कर लिखित परीक्षा पास की थी। आरोपित ने आठ लाख रूपए में सौदा करके पेपर लेकर लिखित परीक्षा तो पास की,लेकिन अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया। एसओजी की

- आरोपी ने लीक सॉल्वड पेपर पढ़कर लिखित परीक्षा पास की थी, पर अंतिम रूप से चयन नहीं हुआ।
- टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) एसओजी वीके सिंह ने बताया कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए परीक्षा से पहले लीक सॉल्वड पेपर पढ़ कर लिखित परीक्षा पास करने वाले आरोपित रिंकू यादव (33) निवासी नगर जिला डींग भरतपुर हाल कामां जिला डींग भरतपुर को गिरफ्तार किया है। एसओजी की जांच में सामने आया कि रिंकू ने कार्तिकेय शर्मा के साथ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कांग्रेस को “वोट चोरी” के बाद “एथनॉल मिक्सिंग” दूसरा सबसे बड़ा स्कैम नज़र आता है

- पूर्व में अध्यक्ष रहे महावीर रांका, शतरंज संघ व सहायता विभाग से जवाब मांगा।

कर जवाब तलब किया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने ये आदेश अशोक कुमार भागव की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता अखिल सिमलोट ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता राजस्थान शतरंज संघ का (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4 सितम्बरा वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने गुरुवार को यहां एआईसीसी मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर जमकर हमला बोला, खासकर एथनॉल नीति और जीएसटी सुधारों में देरी को लेकर। उन्होंने जीएसटी सुधारों में आठ साल की देरी पर मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अब सरकार आखिरकार राहुल गांधी की लंबे समय से दी जा रही सलाह को मान रही है। राहुल गांधी ने गरीबों और व्यापारियों पर जीएसटी के प्रभाव की पुनर्समीक्षा की मांग की थी। उन्होंने कहा, आज एथनॉल पर हम थोड़ी बात करेंगे, काफी दिनों से चर्चा चल रही है इथेनॉल पर और एथनॉल पर

कांग्रेस के मीडिया व पब्लिसिटी चेयरमैन पवन खेड़ा ने प्रैस कॉन्फ्रेंस करके इस नए स्कैम को साबित करने के लिये काफी आंकड़ेबाजी की

- खेड़ा के अनुसार, सात साल हुए जब भाजपा ने “एथनॉल” पेट्रोल में मिलाकर, पेट्रोल के दाम गिराने का दावा किया था, पर सात साल बाद आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ।
- भारत का प्रारंभिक वादा था, नगर पालिकाओं से निकले “वेस्ट” को एकत्रित कर उससे एथनॉल बनाया जायेगा। जिसे पेट्रोल व डीजल में मिलाकर बेचा जायेगा और पेट्रोल 55 रु. लीटर के भाव बिकेगा और इसलिये सरकार एथनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित करने जा रही है।
- पर सात साल बाद भी म्युनिसिपल वेस्ट व लकड़ी के बुरादे से एक लीटर एथनॉल भी नहीं बना है।
- इसी प्रकार यह भी वादा किया गया था, कि एथनॉल के उपयोग से प्रदूषण कम होगा, जबकि सच तो यह है कि लीटर एथनॉल बनाने के लिये तीन हजार लीटर पानी की खपत होती है। इससे पर्यावरण का फायदा है या नुकसान।
- खेड़ा ने यह भी आरोप लगाया कि भारत में निर्मित वाहनों में एथनॉल मिश्रित पेट्रोल के इस्तेमाल से, इंजन बहुत जल्दी फुंक जाता है।

जमानती अपराध पर महिला आरोपियों को 43 दिन जेल में रखना खेदजनक

जयपुर, 4 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानती अपराध होने के बावजूद, महिला आरोपियों का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर जेल भेजने तथा उन्हें 43 दिन तक जेल में रखने पर खेद जताया है। इसके साथ ही, अदालत ने न्यायिक मजिस्ट्रेट और एडीजे क्रम-6 महानगर द्वितीय की ओर से पेश स्पष्टीकरण से असंतुष्ट होते हुए रजिस्ट्रार को आदेश दिए हैं कि वे प्रकरण को

- हाई कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारी मशीनी अंदाज में जमानत प्रार्थना पत्र नहीं निपटायें।
- जानकारी जिले के गार्जियन जज को दें। वहीं अदालत ने डीजीपी को कहा है कि वे संबंधित जांच अधिकारी से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांग कर आगामी कार्रवाई करें। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को भी कहा है कि यदि उन्हें लगता है कि प्रकरण में उनके मौलिक अधिकारों की अवहेलना हुई है तो वे कानूनी प्रावधानों का सहारा ले सकती हैं। जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने ये आदेश मीतू पारीक और इंदू वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। सुनवाई के दौरान, न्यायिक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ट्रैक्टर लेकर विधानसभा पहुंचे

कई विधायक बारिश से खराब हुई फसल भी लेकर आये

जयपुर, 4 सितम्बरा। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को, भारी बारिश से खराब हुई फसलों के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष में बैठे कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सदन में नारेबाजी की, वैंल में आकर विरोध जताया और स्पीकर से भी तीखी बहस की। हालात इतने बिगड़े कि सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। दूसरी बार की कार्यवाही महज 33 मिनट ही चल सकी। हंगामे के बीच तीन बिल पास करवाए गए और फिर कार्यवाही सोमवार, 8 सितंबर तक के

- आपदा राहत मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस विधायकों के हंगामे के बीच स्थगन प्रस्तावों का जवाब दिया।

लिए स्थगित कर दी गई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली खुद ट्रैक्टर लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। इसके बाद कांग्रेस

सुप्रीम कोर्ट ने माना उत्तरी राज्यों में भारी बाढ़ का प्रमुख कारण पेड़ों की अवैध कटाई है

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मीडिया रिपोर्ट्स में बाढ़ में लकड़ी के बड़े-बड़े लट्ठे बहते हुए दिख रहे हैं, ऐसा लगता है पहाड़ों पर पेड़ों को अवैध रूप से काटा जा रहा है

- जाल खंबाता- -राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 4 सितम्बरा सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और पंजाब में बाढ़ और भूस्खलन से हुई तबाही पर गहरी चिंता जताई और पहाड़ी इलाकों में “पेड़ों की अवैध कटाई” को इसका प्राथमिक कारण माना। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के दौरान बहती लकड़ियों के वीडियो फुटेज का हवाला देते हुए कहा, “यह एक गंभीर मामला है। मीडिया रिपोर्ट्स में देखा गया है कि बाढ़ में भारी मात्रा में लकड़ी के लट्ठे बहते हुए नजर आए। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि पहाड़ों में पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है। पीठ ने केंद्र सरकार को – पर्यावरण मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से – और साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनडीएमए) तथा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर की सरकारों को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके बाद इस मामले की आगे सुनवाई होगी।
- सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय, जलशक्ति विभाग, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल हाइवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर व उत्तराखंड सरकार को नोटिस भेजकर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। उसके बाद आगे सुनवाई होगी।

(एनडीएमए) और न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर की सरकारों को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके बाद इस मामले की आगे सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश ने चिंता व्यक्त (शेष अंतिम पृष्ठ पर)



नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली गुरुवार को बारिश से खराब हुई फसलों और किसानों की अनदेखी पर विरोध जताने के लिए ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा परिसर पहुंचे।

विधायक पैदल मार्च करते हुए विधानसभा के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कई विधायक अपने हाथों में, भारी बारिश के कारण खराब हुई फसलें भी लेकर आए थे, ताकि सरकार को जमीनी हकीकत से रूबरू कराया जा सके। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों ने अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसलें भी लेकर आए थे, ताकि सरकार को जमीनी हकीकत से रूबरू कराया जा सके। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों ने अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का मुद्दा उठाया। विधायक अमित चाचाण और नरेन्द्र बुढ़ िनिया ने कहा कि लाखों एकड़ में फसलें खराब हो चुकी हैं, लेकिन सरकार ने अब तक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली में राहत कैंप भी पानी में डूबा

- यमुना का पानी खतरे के निशान से सवा दो मीटर ऊपर तक पहुंच गया है।

इसकी वजह से दिल्ली और नोएडा के कई इलाके डूब गए हैं। जानकारी के मुताबिक, मयूर विहार फेज-1 का राहत शिविर भी बाढ़ के पानी में डूब गया है। रिंग रोड, अलीपुर, बुराड़ी, मयूर विहार, रिंग रोड समेत कई इलाकों में भी बाढ़ का पानी पहुंच गया है। यमुना बाजार, सिविल लाइन्स समेत कई एरिया भी बाढ़ से (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

यह मेरा है-यह तेरा है ऐसा संकीर्ण हृदय वाले मानते हैं। उदार चित्त वाले तो सारे संसार को एक कुटुंब समझते हैं। –हितोपदेश

क्या संविधान के अनुसार सांसद व विधायक

पेंशन प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं?

विधानसभा सदस्यों तथा संसद के सांसदों को वेतन व परिलब्धियां, भत्ता व पेंशन मिलती है। वेतन भत्ता व पेंशन अधिनियम, 1954 है। राजस्थान राज्य के अधिकारियों व विधायकों के वेतन भत्तों व पेंशन का अधिनियम, 1956 (Act No.6 of 1957) है। यहां यह उल्लेख करना समीचीन व आवश्यक है कि इन दोनों कानूनों में प्रारम्भ में जब ये बनाये गये पेंशन देने का कोई प्रावधान नहीं था। इनमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं। राजस्थान राज्य ने अधिनियम के तहत रूल्स बनाये हैं जो राजस्थान विधानसभा सदस्य नियम, 1977 हैं।

सेलेरीज एण्ड एलउन्सेज अधिनियम, 1954 को संशोधन किया गया और उसमें मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट शब्दावली को जोड़ा गया। इसे नई धारा 8ए से जोड़ा गया, जिसके द्वारा पेंशन देने की व्यवस्था की गई। इसका स्पष्ट अर्थ था सांसदों को वेतन भत्तों के अतिरिक्त पेंशन भी प्राप्त होगी। पेंशन की रेट में कई बार संशोधन कर वृद्धि की गई।

राजस्थान में केन्द्र के अधिनियम, 1954 की भांति विधानसभा के अधिकारियों व विधायकों को वेतन व परिलब्धियों के साथ पेंशन दिये जाने का प्रावधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। पेंशन का प्रावधान राजस्थान एक्ट नं. 17/2015 व संशोधन एक्ट 26/2017 से धारा 4क के रूप में जोड़ा गया। इस प्रावधान में यह व्यवस्था है कि 1 अप्रैल, 2019 से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो सदस्य 5 वर्ष तक की कालावधि के लिये निरन्तर या अन्यथा पांच वर्ष तक की कालवधि के रहा हो, उसे 35,000/-रूपये पेंशन दी जावेगी और उपर्युक्त पाँच वर्ष की कालावधि (टर्म) से अधिक पूरे टर्म के लिये हो तो 1600/-रूपये की अतिरिक्त पेंशन प्रतिमाह सदलत की जावेगी। सदस्य 70 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेता है तो उसे 20 प्रतिशत तथा 80 वर्ष पर 30 प्रतिशत की वृद्धि होगी। प्रावधान 4ख में कुटुम्बिक पेंशन की बात है। यदि विधानसभा 5 वर्ष से पहले विघटित कर दी गई हो तो भी अवधि कम होने पर भी पेंशन देने के हेतु अवधि को 5 वर्ष मान लिया जावेगा। यदि सांसद व विधायक कोई संवैधानिक पद धारण करता है तो पेंशन की अदायगी सस्पेंड रहेगी।

सांसद हो अथवा विधायक 5 वर्ष के कार्यकाल समाप्त होने पर एक साधारण नागरिक की भांति हो जाता है। वह पुनः चुनाव लड़ सकता है, विधायक/सांसद बन सकता है। विधायक/सांसद रिटायर नहीं होता। पेंशन को रिटायरल बेनीफिट कहा जाता है। अधिकारी व सांसद/विधायक में अन्तर है। अधिकारी कर्मचारी है; किन्तु सांसद/विधायक जनता द्वारा Elect किये जाते हैं। साधारण रूप से जिस व्यक्ति ने सरकारी नौकरी की है अथवा जिसे सरकारी संस्थानों में जिन्हें स्टेट कहा जाता है नौकरी की है और सेवा की शर्तों के अनुसार पेंशन की व्यवस्था है उन्हें पेंशन दी जाती है। विधायक व सांसद जैसा ऊपर कहा है, रिटायर नहीं होते हैं उनका केवल टर्म समाप्त होता है और वे चुनाव में जीतने पर पुनः सदस्य बन सकते हैं। नगरपालिका, पंचायत जैसे निकायों में भी चुनाव होते हैं यह चुनाव भी निश्चित अवधि में होते हैं। वहां भी सदस्य, रिटायर नहीं होते हैं वे पुनः चुनाव लड़ सकते हैं, वहां पेंशन का कोई प्रावधान किसी भी कानून में चाहे वह पंचायत एक्ट हो अथवा यूनिसिपिलिटी एक्ट (अधिनियम) नहीं है। फिर क्यों विधायकों/सांसदों को पेंशन दी जावे? यह एक विचारणीय प्रश्न है, अतः हमें संविधान को देखना होगा, पढ़ना होगा उसका अध्ययन करना होगा कि क्या पेंशन का उपरोक्त प्रावधान जो उक्त कानूनों में संशोधन द्वारा जोड़ा गया है वह संवैधानिक है? साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि पेंशन किसे दी जावे, इसकी क्या व्यवस्था है? सबसे अधिक महत्व की बात यह है कि हमें पेंशन शब्द की जो परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366(1) में दी है, उसकी सही व्याख्या क्या है?

हम सब देश के नागरिक हैं, यहां लोकतंत्र है। देश के लोगों ने संविधान बनाया है। देश के संचालन के लिये, नागरिकों के जीवन की सुरक्षा के लिये उनके गरिमा मय जीवन यापन के लिये, खाद्य, चिकित्सा, देश की सुरक्षा आदि के लिये फण्ड की आवश्यकता है जिसे टैक्स लगाकर ही पूरा किया जा सकता है। अतः सरकार के फण्ड का खर्च विवेकपूर्ण होना चाहिये और संविधान द्वारा मान्य भी। सरकार द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार सन् 2021-22 में उस वर्ष 25 करोड़ 95 लाख 47 हजार 400/-रूपये का पेंशन पर खर्च था।

लेखक, पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है जो सबको झकझोर देगा कि विधायक को प्रत्येक विधानसभा के टर्म की राजस्थान में पेंशन दी जाती है। यदि कोई विधायक कई बार विधायक बनता है तो उसे उतनी ही बार की बढ़ी पेंशन मिलेगी। क्या इसका कोई औचित्य हो सकता है? यह पेंशन वर्तमान में दिनांक 1.4.2023 से 31,000/-रूपये प्रति माह है। हाँ, यदि वह दूसरे टर्म के हेतु चुनाव जीतकर सांसद बनता है तो उसे बैसिक पेंशन 31,000/-रूपये व अतिरिक्त पेंशन 5 वर्ष के टर्म लिये रु. 2,500 X 5 = रु. 43,500/- मिलेगी। सांसदों व विधायकों को वेतन के अतिरिक्त कई तरह के भत्ते दिये जाते हैं और फिर भी पेंशन। इनमें बदलेतरी होती रहती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। राजस्थान में विधयक के दूसरे टर्म की पेंशन रु. 43,000/- है और प्रत्येक टर्म में अमर्यादित रूप से बढ़ जाता है।

आइये, इस पृष्ठभूमि में हम संविधान के परिप्रेक्ष्य में पेंशन को जो सांसद व विधायक प्राप्त कर रहे हैं उसका कानूनी परीक्षण करें। संविधान के अनुच्छेद 106 में सांसदों को वेतन व भत्ते दिये जाने का प्रावधान है, जिनका निर्धारण व प्रबन्ध समय-समय पर अधिनियम बनाकर संसद करती है। इसी प्रकार विधायकों के वेतन व भत्तों के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 195 के प्रावधान हैं। अधिनियम (एक्ट) के द्वारा वेतन व भत्ता दिया जाता है। इन दोनों प्रावधानों में पेंशन दिये जाने का कोई व्यवस्था नहीं है। इसका सामान्य भाषा में अर्थ है कि संविधान सांसदों व विधायकों को पेंशन देने के बाबत अधिनियम बनाकर मनमानी कानून बनाने की अनुमति नहीं देता।

उपरोक्त कथन को बल इससे भी मिलता है जब हम संविधान की सूची 1 की एन्ट्री 73 को सांसदों के वेतन व भत्ते के बाबत कानून बनाने की अनुमति देता है। इसी प्रकार राज्य की सूची 2 की एन्ट्री 38 है जो विधायकों के भत्ते व वेतन के हेतु कानून बनाने की अनुमति देता है। सूची 1 की एन्ट्री 73 व सूची 2 की एन्ट्री 38, क्रमशः सांसदों व विधायकों को पेंशन देने की अनुमति नहीं देती है। अर्थ स्पष्ट है उपरोक्त दोनों कानून और उसमें हुये संशोधन अवैध, असंवैधानिक, अमान्य व शून्य है।

पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने राजस्थान में वेतन संशोधन अधिनियम, 2017 के द्वारा राजस्थान मंत्री अधिनियम 1956 में संशोधन के द्वारा धारा 7 बीबी व धारा 11(2) जोड़कर पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन सरकारी आवास व 10 व्यक्तियों का स्टाफ व ड्राइवर की सुविधा प्रदान की गई थी, साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया था कि मुख्यमंत्री ने अपने निर्धारित पांच वर्ष की अवधि पूरी नहीं की तो भी यह सुविधा उन्हें प्राप्त होगी। इस प्रावधान को राज्य के वरिष्ठ व यशस्वी पत्रकार मिलापचंद डांडिया ने एक पीआईएल रिट याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिसकी फीली प्रसिद्ध एडवोकेट विमल चौधरी ने की थी। यह याचिका दिनांक 4.8.2019 के आदेश से उच्च न्यायालय से स्वीकृत हुई और उक्त प्रावधान को अवैध करार दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रावधान को निरंकुश व औचित्यहीन करार दिया। इसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में एएलपी दायर की गई, किन्तु उसे 6.1.2020 को एडमिशन स्टेज ही पर खारिज किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय की डीबी का उक्त निर्णय प्रस्तुत केस पर भी लागू होता है। यहाँ भी पेन्शन का प्रावधान निरंकुश, मनमाना अमर्यादित व समाप्ता के सिद्धान्त के मूल अधिकार के विरुद्ध है। सांसदों, विधायकों, अधिकारियों को वेतन, भत्ता आदि दिये जाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है; किन्तु जब इनका भुगतान संविधान की मर्यादा की सीमा लांघकर निरंकुश, विवेकशून्य और विभेदकारी हो कर फ्रीबीज व लूट का रूप धारण करता है तो जनता का विरोध करना स्वाभाविक है।

सुप्रीम कोर्ट ने डी.एस. नकारा बनाम भारत संघ (1983) 1 एसएससी 305 के केस में यह विचार अभिव्यक्त किया है कि पेंशन चेरिटी नहीं है अपितु कर्मचारी द्वारा जीवन में की गई मेहनत का फल है। यह रिटायरमेंट के बाद दिया गया एक अधिकार है सांसद रिटायर नहीं होता। यह स्वीकृत सिद्धान्त है कि पेंशन सोशल सिक्युरिटी है, जबकि सांसद अपने टर्म की समाप्ति पर (जो 5 वर्ष की अवधि का होता है) रिटायर नहीं होते अपितु संसद की सीट रिक्त होती है और वह सदस्य की निरहता (Disqualification) अनुच्छेद 101 में मानी जाती है। वह स्थान चुनाव द्वारा भरा जाता है। सांसद को दुबारा चुनाव में खड़ा होने का अधिकार होता है। पेंशन अधिक आयु होने पर रिटायर होने पर दी जाती है। विधायकों रिटायर नहीं होती उनकी सीट अनुच्छेद 190 के अनुसार रिक्त होती है सदस्य को निरहता का प्रावधान अनुच्छेद 191 के अनुसार होती है। सदस्य यदि लाभ का पद धारण करता है तो वह निरहित होगा। पेंशन पाना लाभ का पद है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जो कॉमन कॉज एक पंजीकृत सोसाइटी है उसमें सांसदों की पेंशन की वैधनिकता का प्रश्न उठाया गया था; किन्तु लेखक का अपना स्वतंत्र विचार है वह निर्णय Precedent नहीं है; क्योंकि उसमें पेंशन शब्द की मूल परिभाषा जो संविधान के अनुच्छेद 366(17) में दी है, उसका उल्लेख ही नहीं है। परिभाषा के अनुसार पेंशन का आधार सेवानिवृत्त वेतन है।

अतः लेखक का मत है कि सांसद व विधायक पेंशन के अधिकारी नहीं है। सेलेरीज एण्ड एलउन्सेज व पेंशन ऑफ पार्लियामेंट अधिनियम, 1954 तथा राजस्थान विधानसभा के अधिकारियों और सदस्यों के वेतन, भत्ता व पेंशन अधिनियम (एक्ट नं. 26/2017) असंवैधानिक, अवैध व निरंकुश, औचित्य शून्य होने से प्रभाव शून्य है तथा निरस्तनीय है। जब विधायकों को दी जाने वाली पेंशन ही असंवैधानिक है फिर अतिरिक्त टर्म की पेंशन तो न केवल विवेक व औचित्य शून्य है अपितु अनैतिक भी है।

यही प्रश्न एक जनहित याचिका (पिटीशन नं. 19134/2022) मिलापचंद डांडिया बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के नाम से राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन है।

सत्यमेव जयते!

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन

पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट



वासुदेव देवनानी

भारत की सनातन सभ्यता में गुरु-शिष्य परंपरा सदैव अत्यधिक प्रतिष्ठित रही है। शिक्षक, चाहे वह प्राचीनकालीन गुरु की भूमिका में हो या वर्तमानकालीन अध्यापक की भूमिका में, न केवल ज्ञान के वाहक हैं, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक नैतिकता, व्यक्तिगत वराष्ट्रीय चरित्र तथा जीवन-मूल्यों के निर्माता भी हैं। हालाँकि आज हम वार्षिक रूप से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं, किन्तु यह उत्सव केवल एक तिथि मात्र नहीं, बल्कि शिक्षक के महत्व और उनके योगदान को याद करने का एक अवसर है। प्राचीन गुरुकुल प्रणाली से वर्तमान विद्यालयी परम्परा तक शिक्षक की भूमिका मेंैक्रमिक परिवर्तनों के बावजूद भी यह एक पवित्र पद माना जाता रहा है।

प्राचीन भारत में प्राथमिक शिक्षण संस्थानों से अधिक केंद्रित रूप था गुरुकुल-जहाँ शिष्य गुरु के आश्रम में निवास करते, न केवल अकादमिक विद्या सीखते, बल्कि जीवनशैली का भी अभ्यास करते थे। इसमें गुरु और शिष्य के बीच गहरा संबंध था, जो केवल पढ़ाई तक सीमित न होकर चरित्र निर्माण,



राजेन्द्र भागवत

इस आलेख का प्रारंभ मैं उस घटना से करना चाहता हूँ जो मुझे मेरे पिताजी ने साठ के दशक में सुनाई थी जब मैं 15 साल का था। यह बता दूँ कि मेरे पिता उदयपुर के महाराणा भोपाल कॉलेज, जो उसे समय इंटर कॉलेज हुआ करता था, में गणित विषय के विख्यात शिक्षक थे। एक बार उन्हें किसी परिचित के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के उदयपुर स्थित आवास पर जाने का अवसर मिला। जैसे ही पिताजी ने अपना परिचय सुखाड़िया जी को देना प्रारंभ किया तो उन्होंने तत्काल खड़े होकर न केवल उनका अभिवादन किया अपितु यह कहा कि—“मैं तो आपको अच्छी तरह से जानता हूँ”। इस प्रकार के सम्मान की कल्पना क्या आज कोई शिक्षक कर सकता है?

मुझे याद है जब पिता जी की आयु लगभग 80 वर्ष की हुई तब उनके शिष्य जो लगभग 70-75 वर्ष के रहे होंगे, वे एक बर उनसे मिलने आते थे, तो उनके चरण स्पर्श कर आदर व्यक्त करते थे। इस प्रकार का रिश्ता शिक्षक और शिक्षार्थी में हुआ करता था, जिसे देखने का सीमांश मुझे मिला। शायद इसी भावना से वे सभी लोग सहमत

आत्म नियंत्रण और नैतिक शिक्षा से जुड़ा था। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की मूल पद्धतियों में शामिल थे- श्रवण (गुरु की वाणी को सुनना), मनन (उस पर बातचीत और चिंतन करना), निदिध्यासन (गहन ध्यान और आत्मसात करना)। वस्तुतः ज्ञान केवल याद रखने या समझने की क्षमता ही नहीं अपितु आंतरिक अनुभूति और आत्म साक्षात्कार भी था।

भारतीय संस्कृति में गुरु को ईश्वर तुल्य माना जाता रहा है। गुरु की महत्ता, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः॥, श्लोक से स्पष्ट है जहाँ उन्हें दिव्यता, मोक्ष और मार्गदर्शन का स्रोत माना जाता है। भारतीय इतिहास परम्परा में गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र वाल्मीकि, संदीपनी, गुरु धौम्य, वेदव्यास, कश्यप, अष्टावक्र, याज्ञवल्क्य, गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान सुधीजन प्रसिद्ध हैं वही भारतीय इतिहास में कौटिल्य जैसे गुरु भी हुए हैं जिन्होंने अखंड भारत निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विदित है कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है, प्रलय व निर्माण उसकी गोद में पलते हैं।

प्राचीन विश्वविद्यालय जैसे तक्षिला, नालंदा व विक्रमशिला में शिक्षक स्वतंत्र रूप से काम करते थे, अपनी पाठशाला चलाते थे और गुरुदक्षिणा की स्वीकारोक्ति पर आधारित व्यवस्था थी, जो अक्सर प्रतीकात्मक होती थी। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल प्रमाण-पत्र नहीं, बल्कि ज्ञान का अंतरण और समाजनिर्माण था।

गुरुकुल और गुरुशिष्य प्रणाली में शिक्षा केवल तकनीकी या अकादमिक नहीं, बल्कि जीवन के विभिन्न आयामों-संस्कार, आत्मअनुशासन,

आध्यात्मिकता, नैतिकता को समाहित करती थी। यह शिक्षा आत्मनियंत्रण और चरित्र निर्माण पर केंद्रित थी।

संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन में गुरु मुख्य भूमिका में रहे हैं। वेद, उपनिषद, दार्शन, धार्मिक कर्मकांड, जीवनशैली का आदान-प्रदान इत्यादि अनेक दृष्टांत हैं जिसके द्वारा भारतीय संस्कृति और मूल्यों को जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखने में शिक्षक अग्रणी रहे हैं। इसके साथ ही यह जानना भी आवश्यक हो जाता है कि सनातन व्यवस्था में स्त्री शिक्षा पर भी उतना ही बल दिया गया जितना पुरुष शिक्षा पर। इसके अंतर्गत वैदिक कालीन विदुषीया दृष्टांत रूप में प्रस्तुत की जा सकती हैं। गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला जैसी विदुषीया वैदिक ऋचाओं की सुजक व आध्यात्मिक चेतना पर संवाद स्थापित करने वाली रहीं। मध्यकालीन भारत में विदेशी आक्रमणकारियों के कारण स्त्री शिक्षा में गिरावट अवश्य आयी, किंतु मीराबाई, संत अक्का देवी, सहजोबाई जैसी सांस्कृतिक शिक्षिकाएँ हुईं जिन्होंने समाज को भक्ति व आत्मानुशासन दिया। पुनर्जागरण काल में सावित्री बाईपहले, रमा बाई, जैसी शिक्षिकाओं ने नारी पुनर्चेतना में अभूतपूर्व योगदान दिया।

आधुनिक समय में परंपरागत गुरुकुल मॉडल का पुनरुद्धार हो रहा है- जैसे नागपुर में श्री वेदविद्यावर्षिनी गुरुकुलम्, जहाँ वेद, संस्कृत, योगशास्त्र, योगध्यान और आचार संस्कार पढ़ाए जाते हैं, और शिक्षा गैरवाणिज्यिक दृष्टिकोण पर आधारित है। गुरुकुलों का पुनरुत्थान गहन आंतरिक विकास की दिशा में एक सांस्कृतिक पहल है, जो व्यावसायिकता से अलग सांस्कृतिक पुनर्चेतना व गौरवशाली इतिहास की पुनर्स्थापना का

माध्यम है।

वर्तमान संदर्भ के अंतर्गत भारत में शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है-जो डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् की जयंती है। डॉ. राधाकृष्णन् स्वयं एक शिक्षाविद, दार्शनिक और विद्वान थे। वे भारतीय ज्ञान परम्परा व दर्शन के संवाहक थे। जब डॉ. राधाकृष्णन से उनके विद्यार्थियों ने उनके जन्मदिवस की धूमधाम से मनाने का आग्रह किया तो नैतिकता से परिपूर्ण सरल व सहजस्वभाव के धनी डॉ. साहब ने कहा कि यह दिवस पूरे देश के शिक्षकों के सम्मान में मनाया जाना चाहिए।

गुरुकुलों का पुनरुत्थान, और गुरुशिष्य संबंध का मौलिक स्वरूप आज की शिक्षा को वैल्यू आधारित दृष्टिकोण से समृद्ध बनाता है। शिक्षक केवल ज्ञान का संचरण नहीं करते, बल्कि संस्कृति, संवेदना, और मूल्य उत्थान का सुअवसर प्रदान करते हैं। शिक्षक दिवस हमें याद दिलाता है कि शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि देश और समाज के नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक युगम का आधार है।

यह दिन हमें शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करने की प्रेरणा देता है। आज की भौतिकवादी प्रवृत्ति व पाश्चात्य शिक्षा के प्रभुत्व के दौर में एक शिक्षक का दायित्व और अधिक बढ़ जाता है। अब शिक्षक एक विषय विशेषज्ञ ही नहीं अपितु कुशल मार्गदर्शक, नेतृत्वकर्ता और सुसंस्कृत व नैतिक मूल्यों की स्थापना करने वाले की भूमिका हैं। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तित्व निर्माण व मूल्य आधारित दृष्टिकोण विकसित करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है।

–वासुदेव देवनानी,
विधानसभा अध्यक्ष,
राजस्थान

“शिक्षक दिवस” पर एक बेबाक विश्लेषण

सम्मिलित होना। इसे उन्होंने ‘वर्गोदय’ शिक्षा का नाम दिया जबकि आवश्यकता सर्वोदयी शिक्षा की थी। उन्होंने इस बात पर विचार करना चाहिए कि शिक्षकों की स्थिति समाज में अब वैसे क्यों नहीं है? क्यों आज समाज में शिक्षकों की वह प्रतिष्ठा नहीं रही एवं क्यों सर्वोच्च प्रतिभाशाली विद्यार्थी शिक्षक नहीं बनना चाहते? सरकार यह कह सकती है कि वह प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को सम्मानित करती है। किंतु यह एक सच्चाई है कि शिक्षकों के ऊपर स्थानांतरण की तलवार सदैव लटककर रखी जाती है। उनके साथ किस प्रकार का अपमानजनक और उपेक्षा पूर्ण व्यवहार शिक्षा प्रशासक और मंत्री गण करते हैं, यह सर्वविदित है। शिक्षकों का अधिकांश समय केवल आँकड़े भरने में और वह सब करने में बीतता है जो शिक्षा से कतई संबंधित नहीं है। शिक्षा विभाग में स्थानांतरण को तो तबादला उद्योग तक कहा जाता है।

सामान्यतः समाज, शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध जीवन पर्यन्त होता है। यह तभी संभव है जब शिक्षक निरंतर एक ही स्थान पर रहे। तब लगातार जुड़ रहे और उसका और विद्यार्थियों का भविष्य भी जुड़ा रहेगा। शिक्षा समाज की आवश्यकताओं से कितनी दूर हो गई है, यह समझने के लिए मुझे उदयपुर जिला भवन के बुनियादी शिक्षा के प्रसिद्ध शिक्षक दयालचंद जी सोनी का स्मरण हो रहा है। दयाल जी ‘माइसाब’ की शिक्षा की दृष्टि स्वर्णीय विकास की थी और उनकी जीवन दृष्टि गांधी और विष्णु से प्रेरित थी। उनके अनुसार मैकाले की शिक्षा पद्धति का एक ही उद्देश्य था- शोषित, वंचित तथा शासित वर्ग- से निकल कर शासक, संपन्न एंड शासक वर्ग में

शिक्षा विद्यालय के बाहर भी होती है घर में भी होती है और वातावरण से भी वह ग्रहण करता है। शिक्षक का कार्य विद्यार्थी को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना होना चाहिए जिसमें वह जिज्ञासु बन सके और अपनी जिज्ञासाओं का उत्तर ढूँढ़ने के लिए खोजी प्रवृत्ति उसमें विकसित हो। क्या हम इस प्रकार का शिक्षक आज तैयार कर रहे हैं? खेद का विषय है कि ऐसा नहीं हो रहा है। अधिकांश शिक्षक आज विद्यार्थियों को केवल कुंजियों या पासबुक के माध्यम से कुछ उत्तर रटकर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के नुस्खे बताते तक सीमित रह गए हैं। जब विद्यार्थी केवल गुटके या पासबुक पढ़कर परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे तो वह किस प्रकार के युवा बनकर निकालेंगे, इसका नमूना हम देख ही रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उचित - अनुचित तरीकों से परीक्षा पास करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य रह गया है चाहे वह स्कूल, कॉलेज की परीक्षा हो या फिर कोई प्रतियोगी परीक्षा।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षकों की भूमिका को अच्छी तरह रेखांकित किया गया है, किंतु उसके लिए आवश्यक है कि सरकार संसाधनों की कमी का बहाना छोड़कर नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए पर्याप्त मानव और वित्तीय एवं मानव संसाधन उपलब्ध कराए। शिक्षा को समुदाय केंद्रित बनाएं। जब तक समाज और शिक्षा एक दूसरे से जुड़े नहीं रहेंगे तब तक ‘ड्राॅप आउट’ की समस्या बनी रहेगी।

बाल श्रमिकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की जो व्यवस्था थी, उसे बहुत पहले ही बंद कर दिया गया है। इसका कारण यह बताया गया कि “जो विद्यार्थी स्कूल में नहीं है वह बाल श्रमिक हैं”। इसका परिणाम यह हुआ की छात्रा प्रतिशत बच्चों का

इंटेलिजेंस व डिजिटल युग में जहां मशीनी प्रवृत्ति का विकास हुआ है, वही एक शिक्षक की भूमिका भी बहुआयामी व चुनौतीपूर्ण हो जाती है कि किस प्रकार वह मूल्य आधारित शिक्षा की स्थापना कर मार्गदर्शक व प्रेरणास्रोत के रूप में प्रकाश पुंज की तरह विद्यार्थियों के समस्त मानसिक, सांस्कृतिक विकारों को दूर कर एक सुशिक्षित, सुसंस्कृत व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करे ताकि भारत की आने वाली पीढ़ी अपने सामाजिक- सांस्कृतिक- आध्यात्मिक मूल्यों को अंगीकृत व आत्मार्पित कर सके।

निष्कर्षतः गुरु-परंपरागत भारतीय शिक्षा प्रणाली के नायक और संस्कृति के संरक्षक रहे हैं। गुरुकुल शिक्षा में ज्ञान और आत्मविकास का समन्वय था; आधुनिक शिक्षा में शिक्षक न केवल अकादमिक ज्ञान देते हैं, बल्कि वे नैतिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक विकास के मार्गदर्शक भी हैं। 5 सितंबर, शिक्षक दिवस के रूप में, हमें यह स्मरण कराता है कि हमारे समाज की नींव और संस्कृति की समृद्धि में शिक्षक कितना अहम योगदान देते आए हैं। इस सम्मानपूर्ण प्रक्रिया को बनाए रखना और भविष्य में शिक्षकों को सम्मान और प्रेरणा का स्रोत बनाना, यही हमारे लिए सर्वोपरि कर्तव्य है। यह दिवस मात्र शिक्षकों को धन्यवाद देने के रूप में ही नहीं बल्कि गुरु- शिष्य के आत्मिक बंधन को सुदृढ़ करने का दिन भी है। साथ ही यह संकल्प लेने का दिन भी है कि यदि राष्ट्र को समृद्ध, सशक्त बनाने है तो शिक्षकों के सम्मान के साथ उनके नैतिक दृष्टिकोण को भी अपनाना है।

–वासुदेव देवनानी,
विधानसभा अध्यक्ष,
राजस्थान

राशिफल शुक्रवार 5 सितम्बर, 2025



पंडित अनिल शर्मा

सिंह, गुरु-मिथुन, शुक्र-कर्क, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।
राज्य सर्वार्थसिद्धि योग सूर्योदय से रात्रि 11:38 तक है। रविवयोग रात्रि 11:38 से आरम्भ होगा। आज प्रदोष व्रत, गोत्रि रात्रि व्रत आरम्भ होगा। आज डा.राधाकृष्ण जयन्ती, शिक्षक दिवस है। आज ईद-ए-मिलाद (बारावफात) है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:47 तक, लाभ-अमृत 7:45 से 10:52 तक, शुभ 12:26 से 1:59 तक, चर 5:06 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:12, सूर्यास्त 6:40

मेघ
व्यावसायिक कार्यों में ध्यान देना ठीक रहेगा। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी।

वृष
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। परिवार में शुभ-मार्गालिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

मिथुन
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

कर्क
परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। आज परिजनो के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

सिंह
स्वास्थ्य संबंधित परेशानी दूर होने लगेंगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।

कन्या
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

तुला
घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।

वृश्चिक
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होगा। परिजनो के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिए दि.अच्छा रहेगा।

धनु
आर्थिक कार्यों से अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। संधावित खेत से धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा।

मकर
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित बाली सफल रहेगी। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आर्थिक परेशानियां दूर होने लगेंगी। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।

कुंभ
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। मन में असंतोष बना रहेगा। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है।

मीन
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दि.अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संधावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

जी.एस.टी. दरों के सरलीकरण पर मुख्यमंत्री भजनलाल ने जताया प्रधानमंत्री मोदी का आभार

गरीब, किसान, व्यापारी और उद्योगपतियों को मिलेगा सीधा लाभ, अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार : भजनलाल शर्मा



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) की दरों के सरलीकरण को लेकर गुरुवार को विधानसभा परिसर में पत्रकार वार्ता की।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) की दरों के सरलीकरण को ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का प्रदेशवासियों की ओर से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, व्यापारी और उद्योगपति सहित समाज के सभी वर्गों को सीधा लाभ मिलेगा और अर्थव्यवस्था को नई गति प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को विधानसभा परिसर में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने बताया कि जीएसटी काउंसिल द्वारा लिए गए निर्णय के तहत अब चार दरों की जगह केवल दो दरें लागू होंगी। यह निर्णय आमजन की जरूरतों-रोटी, कपड़ा और मकान-को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह कदम आर्थिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा और साहसिक निर्णय है, जो न केवल कर प्रणाली को सरल बनाएगा बल्कि पारदर्शिता और व्यापार सुगमता को भी बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि इस बदलाव से प्रदेश के व्यापारियों को जहां राहत मिलेगी, वहीं आम जनता को भी आवश्यक वस्तुओं पर कम टैक्स का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा

साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की अंत्योदय की भावना को साकार करते हुए अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार विकास और जनकल्याण की दिशा में लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। शर्मा ने विश्वास जताया कि जीएसटी दरों के इस सरलीकरण से न केवल करदाताओं का विश्वास बढ़ेगा, बल्कि यह आगामी दीपावली को भी विशेष बना देगा, जब उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत और बाजारों को रफ्तार मिलेगी। यह निर्णय, देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकारों की साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

राज्य की सभी आंगनबाड़ी बनेंगी “आदर्श” : दिया कुमारी

जर्जर भवन होंगे तत्काल स्थानांतरित, एक सप्ताह में मांगी रिपोर्ट



उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को शासन सचिवालय में अधिकारियों की बैठक लेकर प्रदेश की आंगनबाड़ियों की दशा सुधारने पर चर्चा की।

जयपुर । राज्य की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को “आदर्श आंगनबाड़ी” के रूप में विकसित करने के लक्ष्य को लेकर उप मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि फील्ड में जाकर कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन सचिवालय में गुरुवार को आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जर्जर और असुरक्षित भवनों को तुरंत ध्वस्त कर आंगनबाड़ी केंद्रों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जिलों में कलेक्टरों के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों का सर्वे कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाए। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव महेन्द्र सोनी, निदेशक वासुदेव मालावत, मुख्य अभियंता (भवन), समग्र शिक्षा अभियान के अधिकारी, प्रभारी नंद घर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं, सभी जिलों के उपनिदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। उप मुख्यमंत्री ने जिलेवार प्रगति की समीक्षा करते हुए बजट के समय बड़ और पारदर्शी उपयोग पर बल दिया।

उन्होंने नाराजगी जताई कि कई जिलों में अब तक परम्परागत कार्य शुरू नहीं हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक सप्ताह में सभी जिलों से कार्यों की अद्यतन रिपोर्ट अनिवार्य रूप से भेजी जाए और आगामी 15 दिनों में पुनः प्रगति की समीक्षा की जाएगी। दिया कुमारी ने कहा कि आंगनबाड़ी भवनों को सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं से युक्त किया जाए। साथ ही, राज्य सरकार के बजट के अतिरिक्त सीएसआर, आपदा सहायता फंड, जिला खनिज फंड और विधायक निधि जैसी योजनाओं के माध्यम से भी संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाए।

कपड़ों की सिलाई बिगाड़ी, टेलर पर लगाया 10 हजार रुपए का हर्जाना

जयपुर । जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-प्रथम ने ग्राहक के पेंट-शर्ट के कपड़ों की सिलाई बिगाड़ने को सेवादोष करार देते हुए मैसर्स रॉयल टेलर्स पर 10 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। आयोग ने टेलर को निर्देश दिया है कि वह पेंट-शर्ट के कपड़ों की सिलाई व उनकी कीमत 5,488 रुपए परिवाद दायर करने की तारीख से 9 प्रतिशत ब्याज सहित परिवादी को भुगतान करे। आयोग के अध्यक्ष डॉ. सुबे सिंह यादव, सदस्य हेमलता अग्रवाल व सदस्य आशुतोष ने यह आदेश विजय कुमार मल्होत्रा के परिवाद पर दिए।

परिवाद में अधिवक्ता हेमंत कुमार गुप्ता ने बताया कि 11 अगस्त 2021 को परिवादी ने शर्ट व दो पेंट का कपड़ा विपक्षी को सिलाई के लिए दिया था। टेलर ने पन्द्रह सौ रुपए सिलाई देकर की और 22 अगस्त तक डिलीवरी देने को कहा।

परिवादी 14 अगस्त को कपड़ों की ट्रायल के लिए गया तो वह ढीले थे और उनकी फिटिंग सही नहीं थी। विपक्षी ने उसे कहा कि वह इन्हें सही कर देगा, लेकिन परिवादी जब सिले कपड़े लेने गया तो वह खराब ही थे। इसलिए उसे विपक्षी से हर्जा-खर्चा सहित कपड़ों की कीमत दिलवाई जाए। इसके जवाब में विपक्षी टेलर ने कहा कि परिवादी 14 अगस्त को ट्रायल के लिए नहीं आया था। वह अपनी सुविधानुसार 28 अगस्त को ट्रायल के लिए आया और 30 अगस्त को डिलीवरी ले गया। कपड़ों की सिलाई 1560 रुपए थी। इसमें से साठ रुपए छूट देते हुए पन्द्रह सौ रुपए ऑनलाइन भुगतान लिया गया। उसने कोई सेवा दोष नहीं किया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के आयोग ने टेलर पर हर्जाना लगाया है।

हैरिटेज निगम जयपुर के वार्ड 63 के उपचुनाव में कांग्रेस की जीत

59 वोट से कांग्रेस उम्मीदवार भानू सैनी ने जीता पार्षद का चुनाव



हैरिटेज निगम जयपुर के वार्ड 63 के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी भानू सैनी की जीत के बाद कांग्रेस पार्षदों ने मुख्यालय पर जश्न मनाया।

जयपुर (कांसं)। नगर निगम हैरिटेज के वार्ड 63 के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी भानू सैनी ने 59 वोट से जीत हासिल की। यहां बागी सीमा मीणा ने बीजेपी प्रत्याशी रितु नंदवाना को तीसरे नंबर पर धकेला। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से हैरिटेज निगम के वार्ड 63 में उपचुनाव की मतगणना पूरी हुई। यहां त्रिकोणीय संघर्ष में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार भानू सैनी ने 59 वोटों से जीत दर्ज करके सबको चौंका दिया। इसका कारण यह है कि राज्य में भाजपा की सरकार है और निगम में भी भाजपा की महापौर डॉ. कुसुम यादव हैं। चुनाव जीतने के बाद भानू सैनी ने कहा कि यह वार्ड की जनता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। आने वाले दिनों में वार्ड का विकास कैसे किया जा सके। इसी मुद्दे को लेकर काम करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। दरअसल, हैरिटेज निगम के वार्ड 63 में पार्षद पद के लिए उपचुनाव की

बागी सीमा मीणा ने बीजेपी प्रत्याशी रितु नंदवाना को तीसरे नंबर पर धकेला

मतगणना पूरी हुई, जिसके लिए कांग्रेस से भानू सैनी, बीजेपी से रितु नंदवाना और पूर्व पार्षद की पुत्रवधू सीमा मीणा भी चुनावी मैदान में थी। जिसकी वजह से मुकाबला रोचक त्रिकोणीय संघर्ष में बदल गया था। इस मुकाबले में कांग्रेसी प्रत्याशी की जहां जीत हुई है, वहीं कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई सुशीला मीणा की पुत्रवधू सीमा मीणा ने बागी चुनाव लड़कर बीजेपी प्रत्याशी रितु नंदवाना को तीसरे नंबर पर धकेल दिया। किशनपोल विधायक अमीन कागजी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से जनता परेशान हो चुकी है। निकाय के उपचुनाव में वोट की चोट देकर जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी

को जानकारी कर तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया है। जिससे जयपुर में किए गए बीजेपी के विकास के दावों की पोल खुल गई है। आने वाले निकाय चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी जयपुर में अपना बोंड बनाकर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। बता दें कि नगर निगम हैरिटेज के वार्ड 63 में कुल 8 हजार 132 मतदाता हैं। जिनमें से बुधवार को पार्षद पद के उपचुनाव में सिर्फ 3745 (46.06 प्रतिशत) मतदाताओं ने अपने मतार्थिकार का इस्तेमाल किया। इनमें भानू सैनी को मौजूद पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की की 1358, सीमा मीणा को 1299 और रितु नंदवाना को 1062 वोट मिले हैं। जबकि 26 मतदाताओं ने नोटा का इस्तेमाल किया है। हालांकि चुनाव परिणाम आने के बाद भी कांग्रेसी पार्षद भानू सैनी का कार्यकाल सिर्फ कुछ महीनों का ही रहेगा। क्योंकि नगर निगम हैरिटेज के मौजूदा बोर्ड का कार्यकाल इसी साल नवंबर में खत्म होने जा रहा है।

गौ-माता को अर्थव्यवस्था से जोड़ना सराहनीय कदम : कलराज मिश्र

जयपुर में गौ-महाकुंभ का शुभारंभ हुआ, 7 सितंबर तक जारी रहेगा

-कार्यालय संवाददाता- जयपुर। विद्याधर नगर स्टेडियम में गुरुवार को देवराहा बाबा गौसेवा परिवार की ओर से गौ-महाकुंभ 2025 का शुभारंभ हुआ। यह महाकुंभ 7 सितंबर तक चलेगा। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। मुख्य अतिथि को शॉल ओढ़ाकर बुके भेंट कर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि, गाय को भारतीय संस्कृति में मां का दर्जा प्राप्त है उनको लेकर इस तरह के आयोजन होते हैं ये सराहनीय कदम है। इसी तरह गौ-माता को अर्थव्यवस्था से जोड़ना भी एक तरह से अच्छा कदम है। गौ महाकुंभ 2025 परंपरा और प्रौद्योगिकी का संगम है।



राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र और आध्यात्मिक प्रवक्ता सद्गुरु रितेश्वर महाराज ने जयपुर के विद्याधर नगर में गौ-महाकुंभ में शिरकत की।

था। आधुनिकता के इस दौर में कृषि क्षेत्र गौण होता चला गया इसी का परिणाम कि आज प्राकृतिक अस्तित्वन बह रहा है। शारीरिक स्वास्थ्य खत्म होता जा रहा है परन्तु अब पुनः इसी कड़ी में पौराणिक संस्कृति की तरफ लौटने के लिए ये गौ महाकुंभ का आयोजन किया गया है। गौमाता के माध्यम से विभिन्न उत्पादों के सृजन का शोध भी किया जा रहा है। भारत सरकार और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राजस्थान सरकार भी इस दिशा में विशेष प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने पिछले बजट सत्र में जो किसान भाई बहन के माध्यम से खेती करेंगे उन्हें 25 हजार का अनुदान देने की घोषणा की है। निश्चित रूप से इससे गौ संरक्षण में वृद्धि होगी और भारत देश में खुशहाली का दौर

वापस आएगा। देवराहा बाबा गौसेवा परिवार के राष्ट्रीय प्रचारक संजय शर्मा तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ सत्यप्रकाश वर्मा ने कहा गौ महाकुंभ में बाएंगे गौ संरक्षण किस तरह किया जाए। हम कई वर्षों से गौ संरक्षण पर काम कर रहे हैं लेकिन गाय केवल हमारे लिए गोशाला का विषय रह गई है। हमारा लक्ष्य उनसे दूर है। गाय का गौबर, दूध, गौमूत्र हमारे जीवन में बेहद उपयोगी जिनसे कपास, जैविक खाद, आधुनिक पशुपालन की तकनीक और गौ स्टार्टअप विकसित हो रहे हैं। इनकी बजट सत्र में जो किसान भाई बहन के माध्यम से वरिष्ठ प्रचारक और गौसेवक शंकर जी कहा कि घोषणा की है। निश्चित रूप से इससे गौ संरक्षण में रह सकते हैं। गाय के धार्मिक पहलू से हम पहले

■ कृषि प्रधान देश भारत में गौमाता का विशेष योगदान, अब पुनः पुरानी संस्कृति की ओर लौटने की जरूरत : मंत्री झाबर सिंह खर्वा

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले बजट सत्र में घोषणा की थी, जो किसान गौवंश से खेती करेंगे उन्हें 25 हजार का अनुदान मिलेगा : यूडीएच मंत्री

से अवगत हैं लेकिन आर्थिक पहलू पर ध्यान दिए बिना गाय का संवर्धन नहीं हो सकता है। गाय के विकास में एसबीआई भी हमारा सहयोगी जिसकी मदद से 2 से 10 करोड़ रुपये तक का लोन आसानी से मिल जाता है। डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, पशुपालन किसी भी तरह का कार्य हो उसमें मदद मिल जाती है। कार्यक्रम में महापौर कुसुम यादव, वृंदावन से आए संजीव कृष्ण ठाकुर महाराज, आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक और गौसेवक शंकर, भाजपा के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज, राजस्थान ग्रामीण बैंक के जनरल मैनेजर रथाम सिंह, एसबीआई के डीजीएम रविशंकर, शिवव्रत जी, गौ महाकुंभ के चेयरमैन डॉ लालसिंह, समन्वयक मुदुल शर्मा, सदस्य डॉ युद्धवीर सिंह बलवदा, डॉ अशोक कुमावत, एस. बी नवगं, सुरेन्द्र अवाना, पूर्ण चौधरी, भरत जयपुरहित , मनीष जैन समेत अन्य गणमान्य मौजूद थे।

जयपुर। कालवाड़ थाना इलाके में कॉम्पिटिशन एंजाम की तैयारी कर रही विवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते फंदे से झूल अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। काफी देर बाद पिता अपने बेटी को बुलाने के लिए कमरे में पहुंचा तो मामले की जानकारी पता चला। जिसके बाद पीड़ित पिता ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतार अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए शव को कांक्टिया अस्पताल के मुर्दाघर भिजवाया। पुलिस ने बताया कि मांचवा के नारी का बास निवासी ज्योति यादव (20) ने अज्ञात कारणों के चलते फंदे से लटककर सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि 3 साल पहले ज्योति की शादी बिंदायका के रहने वाले योगेश यादव से हुई थी। शादी के बाद भी वह अपने पिता बाबुलाल के साथ रहकर कॉम्पिटिशन एंजाम की तैयारी कर रही थी। बुधवार सुबह नाश्ता करने के बाद वह अपने कमरे में वापस चली गईं। कमरे में जाने के बाद उसने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। करीब 2 घंटे बाद पिता बाबुलाल किसी काम से ज्योति को बुलाने के लिए कमरे में गए तो उन्हें ज्योति फंदे से लटकी मिली। पुलिस को मृतका के पास से किसी भी तरह का कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस अज्ञात कारणों की जांच करने में जुटी है।

पोस्टमार्टम के लिए शव को कांक्टिया अस्पताल के मुर्दाघर भिजवाया। पुलिस ने बताया कि मांचवा के नारी का बास निवासी ज्योति यादव (20) ने अज्ञात कारणों के चलते फंदे से लटककर सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि 3 साल पहले ज्योति की शादी बिंदायका के रहने वाले योगेश यादव से हुई थी। शादी के बाद भी वह अपने पिता बाबुलाल के साथ रहकर कॉम्पिटिशन एंजाम की तैयारी कर रही थी। बुधवार सुबह नाश्ता करने के बाद वह अपने कमरे में वापस चली गईं। कमरे में जाने के बाद उसने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। करीब 2 घंटे बाद पिता बाबुलाल किसी काम से ज्योति को बुलाने के लिए कमरे में गए तो उन्हें ज्योति फंदे से लटकी मिली। पुलिस को मृतका के पास से किसी भी तरह का कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस अज्ञात कारणों की जांच करने में जुटी है।



राजधानी जयपुर में पिछले चार दिनों से चल रहा बारिश का दौर गुरुवार को भी जारी रहा इस दौरान तेज हवाओं और बारिश से सवाईमानसिंह हॉस्पिटल के ट्रामा सेंटर के बाहर एक विशाल पेड़ धराशायी हो गया जिसे काटकर मौके से हटाया गया।

सुरुचि सिंह महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल रैंकिंग में शीर्ष पर

नई दिल्ली, 4 सितंबर। इस वर्ष शानदार प्रदर्शन करने वाली भारत की सुरुचि सिंह महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल रैंकिंग में विश्व में नंबर वन निशानेबाज बन गई हैं। अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ (आईएसएसएफ) द्वारा बुधवार को जारी ताजा अपडेट के अनुसार इस साल की शुरुआत में सीनियर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदार्पण करने के बाद 19 वर्षीय सुरुचि सिंह ने 4162 अंकों के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल में विश्व में नंबर वन रैंकिंग हासिल की। चीन की पूर्व जूनियर विश्व चैंपियन याओ कियानक्सुन ने 3195 अंकों के साथ इस वर्ग में दूसरे तथा चीन की वेई कियान 2178 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

शानदार फॉर्म में चल रही सुरुचि सिंह ने हाल ही में एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित और महिला टीम स्पर्धाओं में दो कांस्य पदक जीते हैं। इसके अलावा उन्होंने इस साल म्यूनिख, लीमा और ब्यूसन आयर्स में हुए तीनों आईएसएसएफ विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते। इसके अलावा लीमा में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिश्रित टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता।

इस बीच, दो ओलिंपिक पदक विजेता मनु भाकर, जिन्होंने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा का कांस्य पदक

जीता था, 1988 अंकों के साथ इस वर्ग में छठे स्थान पर हैं। 25 मीटर एयर पिस्टल रैंकिंग में मनु भाकर 1800 अंकों के साथ चौथे तथा हमवतन ईशा सिंह 1512 अंकों के साथ छठे स्थान पर हैं। पिछले महीने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल श्री पोजीशन में स्वर्ण पदक जीतने वाली ओलींपियन सिफ्ट कौर समरा 3034 अंकों के साथ इस वर्ग में दूसरे स्थान पर पहुंच गई, जबकि आशी चौकसे 1277 अंकों के साथ 10वें स्थान पर हैं। दो बार की ओलिंपियन नर्वे की जीनेट हेग डुएस्टेड 3320 अंकों के साथ महिलाओं की 50 मीटर राइफल श्री पोजीशन रैंकिंग में शीर्ष पर हैं।

अमीन पठान ने किया खेल प्रकोष्ठ अध्यक्ष का पदभार ग्रहण



जयपुर, 4 सितंबर। राजस्थान कांग्रेस कमेटी खेल प्रकोष्ठ के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री अमीन पठान ने आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा नेता, प्रतिपक्ष टीकाराम जुली और कई कांग्रेस विधायकों की मौजूदगी में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन पर पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर प्रदेश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक भी मौजूद रहे। पीसीसी मुख्यालय के बाहर हुए विशाल समारोह में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने अमीन पठान को शुभकामनाएं और बधाई देते हुए कहा कि पठान कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे और खेल और खिलाड़ियों के हितों के लिए भाजपा को इस निकम्मी सरकार को सबक सिखाने के लिए सड़कों पर संघर्ष करेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली ने कहा कि भाजपा की सरकार ने अमीन पठान को बेवजह प्रताड़ित किया और इन पर कई तरह के मुकदमे लगा दिए लेकिन यह डरे नहीं और इस निकम्मी नफरती सरकार से डट कर मुकाबला कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अमीन पठान अकेला नहीं हैं पूरी कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है इस भाजपा की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है।

आरसीए की एजीएम आज एजीएम में राज्य के पूर्व टेस्ट खिलाड़ियों व बीसीसीआई, आरसीए के पूर्व खेल प्रशासकों को दी जाएगी श्रद्धांजलि



जयपुर, 4 सितंबर। आरसीए एडहॉक कमेटी संयोजक डी डी कुमारवत के अनुसार राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एजीएम (नार्षिक आम बैठक) कल दिनांक 5 सितंबर 2025 को जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम स्थित आरसीए ऑफिस, आरसीए अकादमी पर दोपहर 1.00 बजे आयोजित की जाएगी। संयोजक डी डी कुमारवत ने बताया कि आरसीए एजीएम की शुरुआत राजस्थान के पूर्व दिवंगत अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट खिलाड़ी स्वर्गीय हनुमंत सिंह , स्वर्गीय पार्थसारथी शर्मा , स्वर्गीय सलीम दुर्रानी व बीसीसीआई – राजस्थान क्रिकेट संघ के विकास में अमूल्य योगदान देने वाले राज्य के पूर्व खेल प्रशासकों स्वर्गीय महाराणा भगवत सिंह, स्वर्गीय पी एम रूंगटा, स्वर्गीय राज सिंह डुंगरपुर, स्वर्गीय कमल मोरारका, स्वर्गीय किशन रूंगटा, स्वर्गीय मानवेन्द्र सिंह, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह राठौर, स्वर्गीय अशोक ओहरी व स्वर्गीय राकेश अग्रवाल को श्रद्धांजलि दी जाएगी।

राजस्थान की छवि, दिव्यांशी, सुभाष और प्रभव सेमीफाइनल में

जयपुर, 4 सितम्बर। राजस्थान की छवि सारण, दिव्यांशी जैन, सुभाष चौधरी और प्रभव बाजोरिया ने गुरुवार को यहां एसएमएस स्टेडियम कोर्ट्स पर खेले जा रही गोल्ड मेडल इंडियन जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में अपनी- अपनी कैटेगरी के सेमी फाइनल में प्रवेश कर लिया। छवि सारण ने अंडर-19 गर्ल्स के क्वार्टर फाइनल में याशी जैन को 12-10, 11-6, 11-9 से हरा सेमी फाइनल में प्रवेश



किया, जहां उसका मुकाबला रुद्रा सिंह से होगा। दिव्यांशी जैन ने गर्ल्स अंडर-13 कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में हराकरी मुकाबले में रिया दलाल को सीधे सेटों में 11-3, 11-3, 11-1 से हरा अंतिम चार में जगह बनाई। सेमी फाइनल में दिव्यांशी का मुकाबला शुक्रवार को शानया परररामपुरिया से होगा। दूसरा सेमी फाइनल करीना शशिकुमार और नंदिकाश्री कलाखवन के बीच खेला जाएगा। वहीं अंडर-13

बॉयज में प्रभव बाजोरिया ने रोहन खुराना को 11-6, 11-8, 11-9 से हरा सेमी फाइनल में कदम रखा। लेकिन इसी कैटेगरी के एक अन्य क्वार्टर फाइनल में राजस्थान के ओम ठाकुर से हार का सामना करना पड़ा। सेमी फाइनल में प्रभव की उम्मेद शयान समतानी से होगी, जबकि दूसरा सेमी फाइनल आमार्य बजाज और अयुदय अरोड़ा के बीच होगा।

आईपीएल सहित प्रीमियर खेलों के प्रशंसकों को जीएसटी का झटका

नई दिल्ली, 4 सितंबर। सरकार के वस्तु एवं सेवा कर सुधार के कदम के तहत कैसिनो, रेस क्लब और इंडियन प्रीमियर लीग जैसे प्रीमियम खेलों के आयोजनों पर जीएसटी दर को 28 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत किये जाने से खेल प्रशंसकों को बड़ा झटका लगा है। नई टैक्स व्यवस्था तहत आईपीएल को प्रीमियर स्पोर्ट्स स्पर्धा में रखा है। इसके तहत टैक्स कैसिनो, रेस क्लब और आईपीएल जैसे प्रीमियम खेल आयोजनों पर अब 40 प्रतिशत जीएसटी देय होगा। इस फैसले के तहत अब आईपीएल मैच की टिकट पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है जिससे अब 1000 रुपये का टिकट पहले की अपेक्षा 120 रुपये महंगा यानी 1400 रुपये में मिलेगा। लेकिन सामान्य क्रिकेट मैचों के टिकटों पर जीएसटी 18 प्रतिशत ही रहेगा। यानी भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया या भारत बनाम इंग्लैंड जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले देखने वालों पर टैक्स का ये नया बोझ नहीं आएगा।

नए जीएसटी प्रावधान से महंगे होंगे आईपीएल टिकट

नई दिल्ली, 4 सितंबर। मैदान में जाकर आईपीएल देखना अब और महंगा हो गया है क्योंकि भारत सरकार ने आईपीएल टिकटों पर लगने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 28 फीसदी से बढ़ाकर 40 फीसदी करने का फैसला किया है। एक हजार रुपए के बेस प्राइस वाले टिकट का जीएसटी के साथ अंतिम दाम अब 1280 से बढ़कर 1400 रुपए हो जाएगा। इस बढ़ोतरी के साथ आईपीएल अब जीएसटी के सबसे बड़े ब्रेकेट में आ गया है जिसमें कैसिनो, रेस क्लब या कोई भी ऐसी जगह जहां कैसिनो या रेस क्लब होते हैं, शामिल हैं। हालांकि देश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच देखने जाने वालों के लिए राहत की संभावना है। इन मैचों के टिकटों पर आईपीएल टिकटों के समान ही 28 जीएसटी लगता था, लेकिन अब यह स्लैब हटा दिया गया है।

प्रेस सूचना ब्यूरो के सर्कुलर में, कर की दर में बदलाव की जानकारी देते हुए, केवल "आईपीएल जैसे खेल

आयोजनों" का ही जिक्र है। वित्तीय और व्यावसायिक प्रकाशनों ने इसका अर्थ यह निकाला है कि अन्य क्रिकेट मैच अब अन्य "मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों" की श्रेणी में आ सकते हैं। अभी तक अन्य मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों के 500 रुपये से अधिक मूल्य के टिकटों पर 18 जीएसटी लगता आया है। 500 रुपए से कम मूल्य के टिकट जीएसटी से मुक्त हैं। इसलिए निकट भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय मैचों और राज्य द्वारा संचालित अन्य लीगों के टिकट सस्ते हो सकते हैं। वर्तमान में यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के टिकट का बेस प्राइस 1000 रुपए है, तो करों को शामिल करने के बाद इसकी कीमत 1280 रुपए हो जाती है।

यह बदलाव 22 सितंबर से प्रभावी होंगे, जो भारत में होने वाले आगले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आयोजन, महिला विश्व कप के शुरू होने से एक हफ्ता पहले है। इस आयोजन के टिकटों की बिक्री अभी शुरू नहीं हुई है। टूर्नामेंट

ऋतुराज गायकवाड़ की शतकीय पारी से वेस्ट जोन बड़े स्कोर की ओर

बेंगलुरु, 4 सितंबर। ऋतुराज गायकवाड़ (184) की शतकीय और तनुष कोटियान (नाबाद 65) की अर्धशतकीय पारियों के दम पर वेस्ट जोन ने गुरुवार को दलीप ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन के खिलाफ छह विकेट पर 363 रन बनाकर बड़े स्कोर की ओर कदम बढ़ा दिया है। आज यहां वेस्ट जोन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी वेस्ट जोन की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट 10 रन के स्कोर पर गंवा दिये। यशस्वी जायसवाल (चार) और हार्दिक देसाई (एक) रन

बनाकर आउट हुए। इसके बाद आर्य देसाई और ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी ने पारी को संभालने का प्रयास किया। दोनों बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिए 82 रनों की साझेदारी हुई। 27वें ओवर में हर्ष दुबे ने आर्य देसाई (39) को आउट कर साझेदारी का अंत किया। श्रेयस अय्यर (25) और शम्भ मुलानी 18 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान ऋतुराज गायकवाड़ एक छोर धामे लगातार रन बनाते रहे। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये तनुष कोटियान ने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ छठे विकेट के लिए 148 रन जोड़े। 75वें ओवर में सारांश जैन ने दोहरे शतक की ओर बढ़ रहे

ऋतुराज गायकवाड़ को विकेटकीपर उषेंद्र यादव के हाथों स्टंप आउट करारकर वेस्ट जोन को बड़ा झटका दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने 206 गेंदों में 25 चौके और एक छक्का लगाते हुए 184 रनों की पारी खेली। दिन का खेल समाप्त होने के समय वेस्ट जोन ने छह विकेट पर 363 रन बना लिये हैं। तनुष कोटियान (नाबाद 65) और कप्तान शार्दूल ठाकुर (नाबाद 24) क्रीज पर मौजूद थे। सेंट्रल जोन की ओर से खलील अहमद और सारांश जैन ने दो-दो विकेट लिये। दीपक चाहर और हर्ष दुबे ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

दोस्त को हराकर सिनर सेमीफाइनल में

न्युयार्क, 4 सितम्बर। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी जैनिन सिनर ने बुधवार को यूएस ओपन में एक और लगभग बेदाग प्रदर्शन किया, जहाँ उन्होंने पहले इतालवी पुरुष मेजर क्वार्टर फाइनल में अपने हमवतन लोरेंजो मुसेट्टी को 6-1, 6-4, 6-2 से हराया। अलेक्जेंडर बुब्लिक को चौथे दौर में हराने के बाद, सिनर ने मुसेट्टी को शानदार अंदाज़ में हराया।

युवराज सिंह ने आईजीपीएल टूर का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया

नई दिल्ली, 4 सितंबर। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग (आईजीपीएल) भारतीय गोल्फ जगत में क्रांति लाने के लिए तैयार है। आईजीपीएल टूर एक अग्रणी पेशेवर सर्किट है जिसमें पुरुष और महिला दोनों एक ही मंच पर प्रतिस्पर्धा करेंगे। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज युवराज सिंह ने आज यहां आईजीपीएल टूर का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में आईजीपीएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तम सिंह मुंडी, एशियन टूर के टूर कमिश्नर/सीओ चो मिन थॉट, भारतीय महिला गोल्फ संघ (डब्ल्यूजीआई) की महासचिव चंपिका सयाल उपस्थित थे। पीजीआई के अध्यक्ष रोमित बोस, भारतीय पुरुष पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी और आईजीपीएल के आइकन खिलाड़ी शिव कपूर और भारतीय पुरुष पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी और आईजीपीएल के आइकन खिलाड़ी एसएसपी चौरसिया भी मौजूद थे।

भारत की 12 सदस्यीय टीम विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भाग लेगी

नई दिल्ली, 4 सितंबर। ओलिंपियन दीपिका कुमारी और कंपाउंड स्टार ज्योति सुरेखा वेन्नम सहित 12 सदस्यीय भारतीय टीम शनिवार से कोरिया गणराज्य के ग्वांगजू में शुरू होने वाली विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भाग लेगी। कोरिया के ग्वांगजू में आयोजित होने वाली इस चैंपियनशिप के लिए भारतीय दल में ओलिंपियन धीरज बोम्मादेवरा और अंकिता भक्त भी 12 सदस्यीय टीम में शामिल हैं। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप पहली बार 1931 में आयोजित हुई थी। 1950 के दशक से प्रत्येक दो वर्ष में इसका आयोजन हो रहा है। भारतीय तीरंदाजों ने इस प्रतियोगिता में 15 पदक जीते हैं। जिनमें तीन स्वर्ण, नौ रजत और तीन कांस्य शामिल हैं। बर्लिन 2023 में आयोजित पिछले संस्करण में तीन स्वर्ण पदक और एक कांस्य पदक जीत कर भारत पहले स्थान पर रहा था।

बर्तवाल ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए विजयी शुरुआत की

लिवरपूल (ब्रिटेन) , 4 सितंबर। भारतीय मुक्केबाज पवन बर्तवाल ने गुरुवार को पुरुषों की 55 किलोग्राम भार वर्ग की करीबी बाउट में ब्राजील के माइकल डगलस ट्विनडे को हराकर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में विजयी शुरुआत की। आज यहां खेले गये मुकाबले में पहले दो राउंड के बाद बर्तवाल और ट्विनडे बराबरी पर थे, लेकिन दूसरे राउंड में ट्विनडे ने बर्तवाल की बढ़त को खत्म कर दिया। इसके बाद बर्तवाल ने तीसरे और अंतिम राउंड में दबाव में अपनी कुशलता का प्रदर्शन करते हुए अपने ब्राजीलियाई प्रतिद्वंद्वी को पछाड़ा।



Jodhpur Development Authority, Jodhpur
E-Auction Programme of Residential, Commercial & Farm House Plots in Jodhpur (Sep. -Dec, 2025)
(नवरात्रि व दीपावली के शुभ अवसर पर भव्य ई—नीलामी)

क्रमांक—एफ46 / नीलामी / 2025 / सितम्बर / 17421576

दिनांक— 03.09.2025

भूखण्डों की भव्य ई—नीलामी

दिनांक 15.09.2025 से 01.12.2025 तक

167	आवासीय, व्यावसायिक एवं फार्म हाउस भूखण्ड
राजीव गांधी नगर में कुल भूखण्ड (221.4 वर्ग मीटर से 445 वर्ग मीटर)	फार्म हाउस में कुल भूखण्ड (1500 वर्ग मीटर से 2580.22 वर्ग मीटर)
15 विवेक विहार में कुल भूखण्ड (41.82 वर्ग मीटर से 1560 वर्ग मीटर)	15 अरणा विहार ग्राम बड़ली में कुल भूखण्ड (96 वर्ग मीटर से 447.5 वर्ग मीटर)
33 रामराज नगर ग्राम चौखा में कुल भूखण्ड (व्यवसायिक) (3179.57 वर्ग मीटर से 6750 वर्ग मीटर)	18 मण्डलनाथ आवास में कुल भूखण्ड (41.80 वर्ग मीटर से 613.15 वर्ग मीटर)
02 ईएमडी जमा दिनांक 15 सितम्बर 2025 से प्रारम्भ	20 विज्ञान नगर में कुल भूखण्ड (92.01 वर्ग मीटर से 679.83 वर्ग मीटर)

ऑनलाईन बिड

प्रारम्भ तिथि: 15 सितम्बर 2025

अंतिम तिथि: 01 दिसम्बर 2025

प्रभारी अधिकारी (नीलामी शाखा) जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर

अधिक जानकारी के लिए QR स्कैन करें।



निदेशक वित्त जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर

फोन:— 0291—2656355, 2656356

नीलामी के समस्त भूखण्डों की विस्तृत जानकारी एवं नीलामी की शर्तें जोधपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट : joda.rajasthan.gov.in पर देखें या कार्यालय में सम्पर्क करें। नीलामी की प्रक्रिया SSOID के जरिये Urban Services के माध्यम से की जाएगी।

मुख्यमंत्री के निर्देश : विधायक अतिवृष्टि क्षेत्र का सघन निरीक्षण करें

प्रभारी मंत्रियों व सचिवों को भी दो दिन जिलों में राहत व बचाव कार्य की निगरानी के निर्देश दिए

जयपुर, 4 सितंबर राजस्थान में अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न हालात को देखते हुए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी विधायकों को 5, 6 एवं 7 सितंबर को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों का सघन निरीक्षण करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि संवेदनशीलता और तत्परता के साथ आमजन की समस्याओं का समाधान करें।

मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्रियों और सचिवों को भी निर्देशित किया है कि वे दो दिन तक जिलों का दौरा कर राहत और बचाव कार्यों की निगरानी करें तथा आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण कराएं। भारी बारिश से बनी स्थिति को लेकर विधानसभा में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष 1 जून से 1 सितंबर तक प्रदेश में औसत से 56 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई है। ऐसे में सभी विधायक अपने क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाएं और जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर राहत कार्यों को गति दें।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि विधायक और प्रभारी मंत्री अपने-अपने क्षेत्रों में जिला कलेक्टर व अन्य अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें

करें और राहत कार्यों की प्रगति की जानकारी लें। साथ ही, प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों का मनोबल बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि निचले इलाकों से समय रहते

■ **मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक नियमित रूप से मीडिया व आम जन को राहत कार्यों की जानकारी दें ताकि किसी प्रकार की अफवाह नहीं फैले।**

महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के लिए सुरक्षित अस्थायी आश्रय की व्यवस्था कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक नियमित रूप से मीडिया और आमजन को राहत कार्यों की जानकारी दें, ताकि किसी प्रकार की अफवाह न फैले। सोशल मीडिया पर भी हेल्पलाइन नंबर और राहत कार्यों की जानकारी साझा की जाए। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा टीमों की तैनाती, पशुओं के टीकाकरण, पेयजल स्रोतों के क्लोरीनेशन, शिविरों में स्वच्छता की निगरानी और लोगों को गंदे पानी से दूर रहने व साफ भोजन-पानी के लिए जागरूक करने के निर्देश भी दिए।

सुप्रीम कोर्ट ने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

करते हुए कहा, “उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब में हमने अभूतपूर्व भूस्खलन और बाढ़ देखी है। पंजाब की तस्वीरों में तो पूरे के पूरे गांव और खेत उजड़ चुके हैं। विकास जरूरी है, लेकिन संतुलन भी जरूरी है।”

“प्रकृति के साथ छेड़छाड़ अब पलटकर सामने आ रही है।”

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को पीठ ने मामले को गंभीरता से लेने को कहा। न्यायालय ने टिप्पणी की, “एसजी साहब, कृपया इस पर ध्यान दें। यह एक गंभीर मामला प्रतीत होता है। भारी मात्रा में लकड़ी के लट्टे बहते देखे गए हैं, जो पेड़ों की अवैध कटाई को दर्शाते हैं।” मेहता ने अदालत को आश्वासन दिया कि वे तुरंत पर्यावरण मंत्रालय के सचिव और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों से बात करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा, “हमने प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ कर दी है कि अब प्रकृति उसका जवाब दे रही है।”

अदालत यह सुनवाई एक जवाहिर याचिका (पीआईएल) पर कर रही थी, जो अनामिका राणा द्वारा दायर की गई थी। याचिका में हिमालयी क्षेत्रों में बार-बार होने वाली आपदाओं के मद्देनजर रोकथाम और सुधारात्मक उपचारों के लिए निर्देश मांगे गए थे। याचिका में कहा गया है कि केंद्र और राज्य, दोनों के पास आपदा प्रबंधन के लिए समर्पित संस्थाएं हैं, फिर भी वे प्रभावी योजना बनाने और लागू करने में विफल रहे हैं। इसके

परिणामस्वरूप नुकसान की मात्रा और आपदाओं की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।

याचिका में विनाश की तीव्रता बढ़ाने वाले कई कारणों की ओर संकेत किया गया – जैसे पहाड़ी सड़कों के लिए निर्धारित नियमावली की अनदेखी, जल स्रोतों पर अतिक्रमण, और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का पालन न किया जाना।

याचिका में यह आरोप लगाया गया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा जल शक्ति मंत्रालय हिमालयी क्षेत्र की नाजुक पारिस्थितिकी और नदियों की सुरक्षा करने के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे हैं।

याचिका में विशेष जांच दल के गठन की मांग की गई है, जो पर्यावरणीय कानूनों और सड़क निर्माण दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की जाँच करें।

इसमें राजमार्ग और सड़क निर्माण परियोजनाओं में हुई गड़बड़ियों और अधिकारियों की भूमिका की जांच की मांग की गई है, तथा स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन करने की बात भी कही है, जो भूस्खलन वाले क्षेत्रों में भूवैज्ञानिक, भू-तकनीकी, पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी संबंधी जांच करें।

याचिका में हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्स्थापना के लिए उपायों की सिफारिश करने की इच्छा जताई गई है, ताकि नागरिकों के मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14 और 21) की रक्षा हो सके।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कोई ठोस कदम नहीं उठाया। बुढ़ा िनया ने आरोप लगाया कि सरकार के मंत्री हेलिकॉप्टर से दौरे कर रहे हैं, लेकिन किसानों की सुघ नहीं ले रहे। उन्होंने कहा कि गोदामों में पानी भर गया है, कई इलाके जलमय हैं, पर सरकार मूकदर्शक बनी हुई है।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों की फसलें दो बार बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन गिरदावरी तक के आदेश नहीं दिए गए। उन्होंने कहा कि सरकार के कानों के पदें खुल जाएं, इसलिए वे जोर से बोल रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सदन में आए जरूर, लेकिन कुछ समय बाद बिना कोई घोषणा किए चले गए।

विधानसभा में जब आपदा राहत मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने स्थगन प्रस्तावों का जवाब देना शुरू किया, तभी विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस विधायक अशोक चांदना बिना अनुमति के बोलने लगे, जिस पर स्पीकर ने आपत्ति जताई। इसके बाद कांग्रेस और भाजपा विधायकों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। स्पीकर ने बार-बार कांग्रेस विधायकों से शांत रहने की अपील की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ।

आपदा राहत मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि अब तक 2.6 मुतकों के परिजनों को 1.04 करोड़ रुपये का मुआवजा बांटा जा चुका है। 22 जिलों में असामान्य, 16 जिलों में अतिरिक्त और 3 जिलों में सामान्य बारिश दर्ज की गई है।

जमानती ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मजिस्ट्रेट और एडीजे क्रम-6 महानगर द्वितीय की ओर से अदालती आदेश की पालना में अपना स्पष्टीकरण पेश किया, लेकिन अदालत उससे संतुष्ट नहीं हुई। अदालत ने कहा कि न्यायिक अधिकारी अपने स्पष्टीकरण में बता रहे हैं कि प्रकरण में गैर जमानती अपराध के तत्व मौजूद थे, लेकिन जमानत खारिज करने के आदेश में इसका कोई उल्लेख नहीं है।

अदालत ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों ने मशीनी अंदाज में जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया। जमानती अपराध में जमानत को अधिकार का विषय माना जाता है, न कि न्यायिक अधिकारी के विवेक का। अदालत ने कहा कि पहली बार जब आरोपी को पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट के लिए यह अनिवार्य है कि वह सभी दस्तावेजों और साक्ष्य पर विचार करें। इस प्रकरण में जांच अधिकारी, दोनों पक्षों के वकील और न्यायिक अधिकारी अपने कर्तव्य के निर्वहन में विफल रहे हैं। कुछ हद तक यह कोर्ट की याचिकाकर्ताओं की हिरासत के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि बड़ी संख्या में जमानत याचिकाओं के लंबित होने के कारण वह प्रकरण को प्राथमिकता से नहीं ले सका।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजेश महर्षि ने बताया कि चित्रकूट थाना पुलिस ने प्रांटीर डीलर को दुष्कर्म के मामले में फंसाते हैं, न कि धमकी देकर उससे तीना लाख रूपय का चेक लेने के आरोप में याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपी 16 जून, 2025 से न्यायिक अभिरक्षा में थीं। जमानती अपराध के बावजूद, उन्हें जेल में रखा गया। वहीं हाईकोर्ट ने उन्हें गंद तीस जुलाई को जमानत दी थी।

■ **सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी। दूसरी बार की कार्यवाही महज 33 मिनट ही हुई। हंगामे में सरकार ने तीन बिल पास कराये।**

स्पीकर ने कांग्रेस विधायकों को फटकार लगाते हुए कहा कि सरकार की तरफ से जवाब दिया जा रहा था, लेकिन आपने सुना ही नहीं। वेल में आकर विधायकों ने मिसबिहेव किया, जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन उसकी भी मर्यादा होती है।

हंगामे और नारेबाजी के बीच विधानसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 12:34 बजे स्थगित की गई, और दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू होने पर, फिर से हंगामे के कारण 33 मिनट बाद स्थगित कर दी गई। अब सदन की अगली बैठक 8 सितंबर को होगी।

राजस्थान की राजनीति में यह घटनाक्रम किसानों की समस्याओं और सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर गहराते राजनीतिक संघर्ष का संकेत है। जहां सरकार दावा कर रही है कि हर पीड़ित को सहायता दी जाएगी, वहीं विपक्ष इसे नकारापी बताते हुए, सड़कों से लेकर सदन तक प्रदर्शन कर रहा है।

सरकार ... सीजन में पहली बार माही बांध के सभी 1 6 गेट खोले

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तंबाकू, कच्चा तंबाकू और तंबाकू अपशिष्ट, सिगार, चेरुट्स, सिगारिलोस, तंबाकू के विकल्प, वातित पेय (एपरेटेड ड्रिंक्स), कार्बोनेटेड पेय (फल-आधारित भी), कैफीन युक्त पेय, 1,200 सीसी (पेट्रोल) या 1,500 सीसी (डीजल) से बड़ी कार, 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलें, यॉट्स (निजी नौकाएँ), निजी उपयोग के लिए विमान, रेंसिंग कार, ऑनलाइन जुआ और गेमिंग प्लेटफॉर्म। इनमें से अधिकांश वस्तुओं पर पहले ही 28 जीएसटी और क्षतिपूर्क उपकर लग रहा था, जिससे कुल कर भार लगभग 40 तक पहुँच रहा था। जीएसटी परिषद ने 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की दरों को समाप्त कर दिया है और संरचना को केवल दो स्लैब में समेट दिया है: 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत।

दुधपेस्ट, साबुन, शैम्पू, छोटी कारें, टेलीविजन, और एयर कंडीशनर जैसी रोजमर्रा की वस्तुएँ अब कम कर – दरों में आएँगी। बहुत सी दवाएँ, दैनिक उपयोग की वस्तुएँ और चिकित्सा-ग्रेड ऑक्सीजन या तो कर-मुक्त कर दी गई हैं या 5 प्रतिशत स्लैब में लाई गई हैं।

अगस्त में 4 गेट खोल कर पानी की निकासी की गयी थी, पर कैचमेंट क्षेत्र से पानी की आवक बढ़ती गयी

उदयपुर, 4 सितम्बर (कासं)। विदाई से पहले, मेवाड़-वागड़ के कई भागों में मध्यम से तेज बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में उदयपुर जिले के खेरवाड़ा में 81 मिलीमीटर बारिश हुई। कई जलाशयों में पानी की आवक लगातार बनी हुई है।

कैचमेंट में अच्छी बारिश होने और पानी की आवक तेज होने पर गुरुवार को बांसवाड़ा जिले में स्थित माही बांध के सभी 16 गेट खोल दिए गए। इस सीजन में पहली बार माही बांध के सभी 16 गेट खोले गए हैं। अगस्त में इस बांध के 4 गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू की गई थी। उसके बाद आवक बनी रही तो पिछले दिनों और ज्यादा गेट खोले गए। लगातार निकासी के बावजूद, पिछले 24 घंटों में कैचमेंट से पानी की

■ **उदयपुर की आयड़ नदी से पिछोला में आवक बनी हुई है। दोनों गेट तीन फीट खोलने के बाद भी उदय सागर का जलस्तर बढ़ रहा है।**

आवक और तेज होने पर पानी की निकासी के लिए बांध के सभी 16 गेट खोल दिए गए।

जलसंसाधन विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों में उदयपुर जिले के खेरवाड़ा में 81 मिलीमीटर, ऋषभदेव में 55, नया गांव में 50, वल्लभनगर में 42, सोमकागदर में 40, सलूंबर में

63, दानपुर बांसवाडा में 65, भदेसर चितौड़ में 48, वागान डेम प्रतापगढ़ में 91 और अरनोदे में 58 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मदार नहर से फतहसागर और सीसारमा नदी से पिछोला में आवक जारी है। आयड़ नदी से उदयसागर में आवक बनी हुई है। दोनों गेट तीन-तीन फीट खोल रखे हैं। उसके बावजूद उदयसागर का जलस्तर बढ़ ही रहा है। पिछले 24 घंटों में उदयसागर के जलस्तर में 2 इंच की बढ़ोतरी हुई है। मादड़ी बांध का गेज 34 फीट के मुकाबले 33 हो गया है। टनल का गेट 6 इंच खोलकर पानी पिछोला में डायवर्ट किया जा रहा है। देवास प्रथम बांध का पानी भी टनल से पिछोला डायवर्ट कर रखा है। देवास प्रथम बांध दो फीट ही खाली है।

अजमेर : बोराज तालाब की पाल में रिसाव, स्वास्तिक नगर के 8 0 मकान खाली कराये

अजमेर, 4 सितम्बर (कासं)।

गुरुवार सुबह से हो रही बरसात से शहर की सड़कें दरिया बनी गईं तो वहीं निचली बस्तियों में पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने आगामी दो-तीन दिनों में तेज बारिश की संभावना जताई है। आम का तालाब क्षेत्र की कॉलोनी में बरसात का पानी भरने से लोग नारकीय जीवन जीने पर मजबूर हो गए हैं। वहीं, बारिश से बोराज तालाब लबालब होने से पाल में आई दरार और रिसाव की आशंका के चलते जिला प्रशासन ने फायसागर रोड स्थित स्वास्तिक नगर कॉलोनी के करीब 80 मकानों को खाली कराया है। प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गये हैं। लगातार बारिश से तालाब की पाल पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे पाल कभी भी टूट सकती है। तालाब क्षेत्र के

जिला प्रशासन को आशंका है कि दरार व रिसाव के कारण तालाब की पाल कभी भी टूट सकती है

■ **तालाब क्षेत्र के बोराज गांव, रावत नगर व स्वास्तिक नगर सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। एन. डी. आर. एफ. और सिविल डिफेंस की टीमें भी तैनात कर दी गई हैं।**

बोराज गांव, रावत नगर व स्वास्तिक नगर सबसे अधिक प्रभावित हैं, कई घरों में पानी भरा हुआ है।

जानकारी के अनुसार, गुरुवार सुबह से तेज बारिश का दौर शुरू हुआ, जो दोपहर तक रिमझिम फुहार के रूप में जारी रहा, जिससे मुख्य सड़कों पर पानी भर गया तथा वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश के अलर्ट को देखते हुए जिला

प्रशासन द्वारा निगरानी रखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार दो-तीन दिन अजमेर संभाग के कई इलाकों में कहीं-कहीं मध्य से तेज बारिश की संभावना है। मानसून के इस सीजन में अब तक एक हजार एमएमए बारिश रिकार्ड की जा चुकी है, जिन कॉलोनियों में बरसात का पानी भरा है, वहां, मडपंप लगाकर पानी की निकासी की जा रही है।

शहर में लगातार हो रही बारिश से

कांग्रेस को “ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्होंने कहा, 2018 से अब तक 7 साल हो गए। वायदे के मुताबिक म्युनिसिपल वेस्ट से या लकड़ी के बुरादे से एक लीटर एथेनॉल भी नहीं बनाया है। और जो 627 करोड़ लीटर एथनॉल बना है, उसमें से 56 प्रतिशत गन्ने से बना है और बाकी अनाज से बना है। कुल 627 करोड़ लीटर एथनॉल में से एक लीटर टी म्युनिसिपल वेस्ट से नहीं बना। ये शॉकिंग है और बहुत हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। जहां तक पर्यावरण के दावे हैं उनकी चौंकाते वाली सच्चाई कुछ और है। एक लीटर एथनॉल बनाने के लिए तीन हजार लीटर पानी की

खपत होती है। ये दूसरा चौंकाते वाला आंकड़ा है। खेड़ा बोले, हमें कहा गया कि साहब एथनॉल से माइलेज बहुत अच्छा होगा और रख रखाव की चिंताएं हैं, खत्म हो जाएंगी पर उट्टा हुआ। नीति आयोग तक माइलेज में 6 प्रतिशत गिरावट स्वीकार करता है, लेकिन हकीकत तो और ज्यादा है। वर्ष 2023 से पहले जितने इंजन हमारे यहाँ बने हैं, वे इंजन डैमेज हो रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता के अनुसार इससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है कि एथनॉल की जो डिस्ट्रीलरीज होती है वो रैड कैटगरी में आती हैं प्रदूषण फैलाने में आगेहोती हैं।

एस. आई. भर्ती ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मिलकर पेपर लीक गैंग के सदस्य विनोद कुमार जाट उर्फ विनोद रेवाड़ से एसआई भर्ती परीक्षा-2021 का लिखित परीक्षा का लीक सॉल्वड पेपर का आठ लाख रुपए में सोदा किया था। दोनों परियों का लीक सॉल्वड पेपर विनोद कुमार रेवाड़ के जरिए कार्तिकेय शर्मा के मोबाइल पर व्हाट्सएप पर लिया था। लीक सॉल्वड पेपर को पढ़ कर रिकू यादव ने एसआई भर्ती परीक्षा की लिखित परीक्षा दी थी। लिखित परीक्षा में हिन्दी विषय में 126.01 और सामान्य ज्ञान विषय में 160.65 अंक, इस प्रकार कुल 286.66 अंक प्राप्त किए थे। लेकिन अंतिम रूप से रिकू यादव का चयन नहीं हुआ। एसओजी ने प्रकरण में अब तक 55

प्रशिक्षु उपनिरीक्षक सहित कुल 126 आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

हाई कोर्ट ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सचिव है। संघ के अध्यक्ष रहे महावीर रांका के खिलाफ सहकारिता विभाग में शिकायत दी गई थी और उन्हें पद से हटाया गया था। वहीं, याचिकाकर्ता ने सहकारिता विभाग में प्रार्थना पत्र पेश कर चुनाव कराने की मांग की थी, जिसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि संघ की जांच विभाग में लंबित चल रही है। याचिका में कहा गया कि इसके बावजूद, वीकानेर में चुनाव कराने के लिए विजित्त का प्रकाशन कराया गया है।

जी.एस.टी. 2.0 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सुधार की कोशिशें पहले से चल रही थीं, लेकिन, मौजूदा आर्थिक हालात में इन्हें तुरंत लागू करने की जरूरत महसूस हुई।

उम्मीद है कि कई वस्तुओं पर टैक्स रेट्स में कटौती और स्लैब पुनर्गठन से घरेलू खपत बढ़ेगी। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के एक बड़े निर्यात बाजार (अमेरिका) में कठिनाइयाँ बढ़ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की टैरिफ नीति से भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार से बाहर हो सकते हैं। कपड़ा और परिधान जैसे बड़े निर्यात क्षेत्र पहले से दबाव में हैं और इन क्षेत्रों में रोजगार तेजी से घट रहा है।

कर कटौती से घरेलू माँग को बढ़ाकर विदेशी बाजारों में हुए नुकसान की भरपाई की जा सकती है। यही तर्क अमेरिका ने पूर्व राष्ट्रपति रीगन के दौर में अपनाया था, जब कर कटौती ने उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूती दी थी। इसी तर्क पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उम्मीद है कि मोटर कार से लेकर दूध उत्पादों तक, टैक्स घटने से घरेलू माँग बढ़ेगी। प्रधानमंत्री भी यही कहते रहे हैं कि सरकार कम कर दरों के जरिए लोगों के पास अधिक पैसा छोड़ रही है ताकि वे अधिक उपभोग पर खर्च कर सकें।

अगर घरेलू खपत बढ़ती है तो यह फायदेमंद हो सकता है। अधिक खपत से उत्पादक निवेश बढ़ाएँगे, निवेश से रोजगार पैदा होगा और फिर विकास की गति तेज होगी। लेकिन आलोचक कहते हैं कि भारत के निजी क्षेत्र का इतिहास बताता है कि बढ़ती माँग हमेशा बड़े निवेश और रोजगार में नहीं बदलती। हाल के वर्षों में भी निजी निवेश कमजोर रहा है और केवल सरकार के बड़े बुनियादी ढाँचे के प्रोजेक्ट्स ने अर्थव्यवस्था को सहारा दिया है।

अगर माँग बढ़ी लेकिन आपूर्ति नहीं बढ़ी तो इसका नतीजा महंगाई हो सकती है और संतुलन बिगाड़ सकता है। यह भी एक संभावना है। फिर भी, रोजमर्रा की

■ **निराशावादियों की इस आशंका के बावजूद वित्त मंत्री ने एक हिम्मत वाली रणनीति अपनाई है और भगवान करे उनका यह रिस्क कामयाबी में तब्दील हो।**

चीजों पर कर में बड़ी कटौती से अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है और निजी निवेश बढ़ सकता है। खासकर मौजूदा समय में, जब निवेश के अवसर खुले हैं और विदेशी कंपनियाँ भारतीय बाजार में निवेश करने आ रही हैं। हाल ही में मोबाइल फोन से लेकर मोटर कार तक विदेशी निवेश में तेजी आई है।

ये वैश्विक कंपनियाँ भारत में विश्वस्तरीय निर्माण कर रही हैं और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी जगह बना रही हैं। साथ ही, ये बेहतर आय वाले रोजगार भी पैदा कर रही हैं। इसलिए मौजूदा सुधारों को सिर्फ कर सुधार नहीं बल्कि सार्वजनिक वित्तीय ढाँचे के बड़े सुधार के रूप में देखना चाहिए। इन्हें मौजूदा भू-आर्थिक हालात और देश पर उनके असर के संदर्भ में समझना होगा। इस दृष्टि से देखें तो यह बदलाव समायुक्त है और विकास को नई दिशा दे सकता है। अब बस इंतजार करना होगा कि नतीजे कैसे सामने आते हैं।

दिल्ली ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रभावित है। वासुदेव घाट, निगम बोध घाट, मोनेस्ट्री और मजनुं का टीला भी पानी में डूब गये हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव चल रही है।